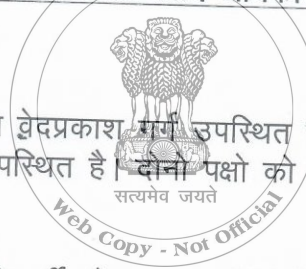


सूचना अधिकार संख्या 55/2016 अनवानी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल निवासी गांव
तहसील व जिला श्रीगंगानगर बनाम श्री हरभजन सिंह, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

12-2016



AB
7

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री वेदप्रकाश शर्मा उपस्थित हैं। जिला रसद अधिकारी के प्रतिनिधि श्री संदीप गोड प्रवर्तन अधिकारी उपस्थित हैं। दोनों पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी के अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध करवाने में कोई रोक नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे।

इसके विपरीत प्रतिनिधि का कथन है कि कोई भी राशनकार्ड धारक अपने से संबंधित प्रविष्टियों की जानकारी ले सकता है। सभी योजनाओं के स्टॉक/वितरण रजिस्टर बाबत उपभोक्त नामले, सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 20.03.2015 जो समस्त भारत में लागू है के खण्ड 10 के उपखण्ड 5 के अनुसार कोई राशनकार्डधारी अपनी सूचना ले सकता है। अन्य किसी को सूचनाएं दिये जाने का प्रावधान नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। अतः अपील अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 16.02.2016 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:-

1. राशन डिपों मदेरों में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवारों की प्रमाणित प्रतिलिपी जो की डिपो को दी गयी है।
2. खाद्य सुक्षरा योजना में डीलर भूपसिंह मदेरों को प्रतिमाह गेहूँ के आवंटन की जनवरी 2015 से जून 2015 तक की प्रमाणित प्रतिलिपी।
3. डिपो मदेरों में डीलर द्वारा वितरण की गई वस्तुओं के रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपी।
4. राशन डिपो को जनवरी 2015 से जून 2015 तक कुल आवंटित कैरोसीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी, प्रत्येक कार्ड पर कितना कैरोसिन दिया जाता है के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी।
5. डिपो मदेरों में वर्ष 2012 से जून 2015 तक प्रतिमाह कैरोसिन जो आवंटित किया गया की प्रतिलिपी जनवरी 2015 से जून 2015 तक वितरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपी।
6. डिपो मदेरों में वर्ष 2012 से जून 2015 तक आवंटित कनक व चीनी जो आवंटित की गई की प्रमाणित प्रतिलिपी जनवरी 2015 से जून 2015 तक वितरण रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपी।

उक्त सूचनाओं के संबंध में अपीलार्थी की अपील पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपना प्रतिवेदन सं० 2555 दिनांक 07.04.2016 प्रस्तुत किया है कि उक्त सूचनाएं कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2"ब" व 7(9) का प्रयोग करते हुए आवेदक का आवेदन निरस्त कर नियत समय अवधि में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 1221 दिनांक 10.03.2016 द्वारा अपीलार्थी को सूचित कर दिया गया था।

जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर ने पत्र सं० 1221 दिनांक 10.03.2016 से अपीलार्थी को सूचित किया गया है:-

AB
2

आप द्वारा चाही गई उक्त सूचनाएं जिस प्रारूप में चाही है कार्यालय में उस प्रारूप में संधारित नहीं है। अतः उक्त सूचना के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2"ब" में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

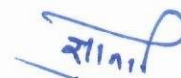
इस प्रकार खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना का अधिकार के तहत नहीं आता। सूचनाएं एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनों को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है। अतः आपका आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

जहां तक भारत सरकार के जिस राजपत्र का सन्दर्भ विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में दिया है का संबंध है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्य सभी विधियों पर प्रभावी है। इसलिए उक्त राजपत्र दिनांक 20.03.2015 के आधार पर सूचना देने से मना नहीं किया जा सकता और न ही इस आधार पर सूचना देने से इन्कार किया है। चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम सभी विधियों पर प्रभावी है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के संबंध में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ही निर्णय लिया जाना चाहिए।

अपीलार्थी द्वारा राशन डिपू मदेरा के खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवारों की प्रतिलिपि, गेहूं एवं मिट्टी के तेल के आवंटन आदेश वितरण रजिस्टर की सूचना चाही है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध अभिलेख के अनुसार चाही गई सूचना अगर सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत देय की श्रेणी में आती है तो वह अवश्य दी जानी चाहिए। इसलिए इस प्रकरण को रिमाण्ड करना उचित समझते हैं। अतः मामला लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करें और प्रत्येक सूचना का बिन्दुवार ही उत्तर दिया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तुरंत तकमिल दाखिल दफतर हो।

8-9
2-117

आदेश आज दिनांक 20.12.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ज्योती राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर